International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 02-12-2022, Accepted: 17-12-2022, Published: 04-01-2023
Volume 9, Issue 1, 2023, Page No. 6-8

भारत में सुशासन के लिए नागरिक सहभागिता में सरकार की भूमिकाः एक सूक्ष्म अध्ययन

अंकित पाण्डेय
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, सिद्धार्थ विश्विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
सुशासन के लिए भागीदारी एक अनिवार्य शर्त हैं । हाल के वर्षो में भागीदारी या सहभागिता लोक प्रशासन के प्रमुख विषय के रूप में अपनी अलग एवं विशिष्ठ पहचान बनाई है । भागीदारी प्रशासनिक गतिविधियों में हर तरह के नागरिक हस्तक्षेप को शामिल करती है । यद्यपि जान भागीदारी तभी सार्थक हो सकती है जब भागीदारी में शामिल नागरिक अपने अधिकारों व उत्तरदायित्व से पूरी तरह वाकिफ हों तथा उन्हें सम्बन्धित कार्ययोजना को पूरी जानकारी हो । भारत में सरकार द्वारा नागरिक सहभागिता के लिए "मेरी सरकार" नामक पोर्टल की शुरुवात करना सरकार का सुशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । जन भागीदारी आम नागरिकों को ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ वह अपनी समस्याओं व जरूरतों व आवश्यकताओं के समर्थन में अपनी सार्थक आवाज बुलंद कर सकता है तथा अपने आप को शासन प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानकर उससे जुड़ा महसूस करता है । प्रशासन में नागरिकों की सहभागिता नागरिकों को सिर्फ मतदान से आगे जाकर अपनी रचनात्मकता व सच्ची नागरिकता को निखारने व संवारने का अवसर प्रदान करती है ।

मूल शब्दः भागीदारी, मेरी सरकार, सुशासन, कार्ययोजना, प्रशासनिक, उत्तरदायित्व, नागरिक, सकारात्मक

प्रस्तावना
सुशासन का विचार नागरिक समाज के विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट करता हैं । शासन का अर्थ होता है विकासोन्मुख तथा जन–जीवन में समानता के सुधार के लिए बाध्य नीतियों की योजना बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने में सरकार की क्षमता । समाज की उर्ध्वगामी चुनौतियों का सामना करने की सरकार एवं नौकरशाही की क्षमता भी शासन कहलाता है । नागरिकों को विशेषकर सीमांत वर्ग की समुन्नति के लिए राजनैतिक प्रणाली के विभिन्न अभिक्रताओं के द्वारा अनेक पर्णधारी को माल उपलब्ध करवाने की योग्यता भी शासन होता है । विधि के नियम के द्वारा कुशासन का विलोपन सुशासन का दूसरा पहलू होता हैं । सुशासन विधि के नियम की स्थापना करता है, व्यक्तियों के बीच संविदाओं एवं करारों का प्रवर्तन करता है । सुशासन कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखता है तथा लोगों की सुरक्षा को सुनिशित करता है, लागत तथा संसाधनों का मितव्यय करता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा समाज को उचित ढंग से सेवाएं प्रदान करता है। यह सरकार के इष्टतम आकार का निर्धारण करता है, सरकारी संसाधनों का सम्भावित उपयोग एवं नागरिक सहभागिता सुनिशित करता हैं ।

सुशासन क्या है ?
सुशासन की विचार के बढ़ते महत्व को स्पष्ट करते हुए टी.के. ओमेंन ने विचार दिया है कि समकालीन शब्दकोश में यह एक चर्चित शब्द बन गया है, वास्तव में यह एक प्रचलित विचार है । सुशासन की संकल्पना विकासशील देशों के द्वारा बनाई गयी तथा लोक प्रशासन के शब्दकोश में यह 1990 में प्रविष्ट की गयी हैं । यह प्रक्रिया मुख्यतः पश्चिमी देशों के द्वारा शीत युद्ध काल के बाद विकासशील देशों को इनके द्वारा दिए गये विकास सहायता के कारण हुआ है ।
1989 में विश्व बैंक ने अपने एक दस्तावेज में, उपसंहारन– अफ्रीकन सन्दर्भ में सुशासन की संकल्पना पर प्रकाश डाला। विश्व बैंक ने सुशासन के चार आयाम को प्रमाणित किया हैः–
1. जन क्षेत्रक प्रबन्धन
2. जवाबदेही
3. विकास के लिए कानूनी ढांचा
4. सूचना एवं पारदर्शिता

इसके बाद 1992 में विश्व बैंक के दस्तावेज में समाविष्ट शासन एवं विकास में यह प्रकट किया गया कि "सुशासन किसी परिवेश का निर्माण तथा भरण पोषण का केंद्र होता है जो प्रबल तथा सामयिक विकास को प्रोत्साहित करता है तथा यह आर्थिक नीतियों को व्यक्त करने में एक अनिवार्य पूरक है ।"
संक्षेप में, विश्व बैंक के अनुसार सुशासन की निर्धारित सीमा इस प्रकार है;–
- राजनैतिक जवाबदेही
- राजनैतिक शक्ति के प्रयोग को न्यायसंगत बंनाने के लिए नियमित चुनाव
- शासन, विकेंद्रीकरण या स्थानीय संगठन का शक्ति के प्रक्रिया में अनेक सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक दलों के द्वारा भागीदारीद्य
- विधि का नियम
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- नौकरशाही की जवाबदेही
- सूचना की स्वतंत्रता
- पर्याप्त एवं प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली
- सरकार तथा नागरिक समाज के बीच सहकारिता

यह सर्वव्यापी स्वीकृत है कि शासन अच्छा होना चाहिए। सुशासन का उद्देश्य है विकास एवं लोग तथा समाज को स्वतन्त्र रूप से सहायता प्रदान करना द्य सुशासन एक गतिशील अवधारणा है जिसमें तीव्रता से बदलता हुआ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तथा प्रकार्यात्मक शासन की स्थितियों सम्मिलित होते हैं। सुशासन संसदीय लोकतंत्र के ढाँचें में लोगो की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने का भी प्रयत्न करता है।
सुशासन के तत्व में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे –
- विधि का शासन
- समानता एवं समावेशन
- भागीदारी
- अनुक्रियाशीलता
- बहुमत/मतैक्य

- प्रभावशीलता
- पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व

नागरिक सहभागिता में सरकार की भूमिका

सुशासन सम्बन्धी आकांक्षाएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। यह सुशासन के लिए दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है जिसके तहत गणतांत्रिक, लोकतंत्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने जनता को सम्प्रभु घोषित किया गया है।

सुशासन के तत्वों में नागरिक भागीदारी या नागरिक सहभागिता का तत्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व साबित होता हैं क्योंकि जब तक सरकारी तंत्र में नागरिकों की सहभागिता स्थापित नहीं होंगी तब तक सुशासन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए प्रत्येक देश की सरकारें शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिशित करने के लिए माध्यम उपलब्ध कराती हैं। भारत में भी सरकार द्वारा नागरिको की सहभागिता के लिए स्थापित करने के लिए "मेरी सरकार" नामक एक पोर्टल की शुरूआत की गयी हैं ताकि जनता सरकार के कार्यों में अपनी राय या विचार प्रदान करे और सरकारी कार्यों में अपनी भागीदारी प्रदान करे। आईये "मेरी सरकार" पोर्टल के बारे विस्तार से समझे ।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां के नागरिक शासन का हिस्सा बनने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण घटक है। "मेरी सरकार–बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं" एक अभिनव प्लेटफार्म है जिसे सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढाने के लिए बनाया गया जिससे सुशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह पहल नागरिकों और दुनिया भर के लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करती है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "मेरी सरकार" पोर्टल का निर्माण भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए किया जहाँ वह सुराज्य प्राप्त करने के लिए अपना योगदान प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अनुसार "लोकतंत्र लोगों की भागीदारी के बिना असंभव है"।

"मेरी सरकार" प्लेटफार्म नागरिकों और विदेशी नागरिकों को चर्चा और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। "मेरी सरकार" पर विभिन्न विषयों पर चर्चाएँ होती हैं जिसमें सभी लोग अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों पर भी चर्चा की जा सकती है जिस पर आप सकारात्मक विचार साझा कर सकते हैं और उस पर दूसरे सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं।

"मेरी सरकार" का लक्ष्य सरकार और नागरिकों को जोड़ना है जिससे देश में सुशासन लाया जा सके। "मेरी सरकार" क्षेत्रीय कार्य करने के इच्छुक लोगों को भी अवसर प्रदान करता है। नागरिक स्वैच्छा से विभिन्न कार्यों के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और इससे संबंधित प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। इन कार्यों का अन्य सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। अनुमोदन के बाद यह कार्य "मेरी सरकार" प्लेटफार्म पर कार्य करने वालों और अन्य सदस्यों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हर अनुमोदित कार्य को पूरा करने पर आप क्रेडिट अंक अर्जित कर सकते हैं।

समूह और कलात्मक क्रियास्थल "मेरी सरकार" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्लेटफार्म पर गंगा की सफाई, हरित भारत, रोज़गार निर्माण, बालिका शिक्षा, कौशल विकास, स्वच्छ भारत जैसे विभिन्न समूह हैं। हर समूह में लोगों को करने के लिए ऑनलाइन और बाहरी कार्य दिए गए हैं। प्रत्येक समूह का उद्देश्य लोगों की भागीदारी के द्वारा उस क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

"मेरी सरकार" पर नागरिक निम्न भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं –

- सरकार, मंत्रालयों और प्रधानमंत्री के अंतर्गत आने वाले विभागों से जुड़ सकते हैं।
- अपनी छुपी क्षमता और प्रतिभा को राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर पहचान दिला सकते हैं।
- नीतियों, कार्यक्रमों और राष्ट्र हितों के मामलों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं।
- विकास और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर अपना सहयोग दे सकते हैं।
- चर्चा पर अपने विचारों को साझा कर और क्रेडिट अर्जित करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं।
- स्वैच्छा से कार्य कर सकते हैं।
- दूसरों के विचार और सुझाव देख सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं।
- "मेरी सरकार" पर सरकार की भूमिका–
- नागरिकों के दृष्टिकोण को समझ कर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
- कार्यों के माध्यम से लोगों के विचार प्राप्त कर सकती है।
- लोगों की प्रतिभा और विशेषज्ञता को पहचान कर उनकी भागीदारी से परियोजनाओं को सफल बना सकती है।
- सर्वश्रेष्ठ विचारो को कार्यान्वित कर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है।

"मेरी सरकार" में कैसे शामिल हो सकते हैं ?

मेरी सरकार पर पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। आपको नाम, अंतिम नाम, ई–मेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड इत्यादि जानकारी प्रदान कर साइन अप करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद आप चर्चा में भाग ले सकते हैं और बाहरी कार्य कर सकते हैं

"मेरी सरकार" प्लेटफार्म नागरिक और सरकार के बीच निम्न माध्यम से सहभागिता को बढावा देते हैं –

1. चर्चा के द्वारा

चर्चा करने के लिए पहले संबंधित समूह में शामिल होना होगा। एक समय में केवल 4 समूह में ही शामिल हो सकते हैं। हर समूह पर चर्चा और कार्य कर सकते हैं। किसी समूह में शामिल होकर लोगों द्वारा संबंधित विषय में व्यक्त किये गए विचार देख सकते हैं। आसानी से अपने समूह में चर्चा के विषय में जानकारी प्राप्त कर उससे सम्बन्धी अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। "मेरी सरकार" पर विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती हैं और सभी लोग उन विषयों पर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सदस्य द्वारा साझा किये गए विचारों पर भी चर्चा की जा सकती है जिसपर आप अपने सकारात्मक विचार एवं प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साझा किये गए विचार और सुझाव अन्य सदस्यों द्वारा पसंद किये जा सकते हैं और उनपर वह अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।

बाद में चर्चा फोरम पर उपलब्ध कराए गए प्रलेखों, विचारों, फोटो, विडियो का मूल्यांकन किया जाएगा।

2. कार्य करे

अभी राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत से कार्य किये जाने हैं। ऐसे कार्य करें जिसमे रुचि हो और भारत के विकास में अपना योगदान दें। लोगों का योगदान ही उनकी भागीदारी का प्रमाण

देता है। "मेरी सरकार" इसके लिए विभिन्न कार्य प्रदान करता है। नागरिक स्वैच्छा से यह कार्य कर सकते हैं। कार्य समाप्त कर उससे संबंधित प्रलेख, फोटो, प्रस्तुति इत्यादि अंतिम तिथि से पहले यहाँ डालने होंगे। कार्य समाप्त होने पर पूर्वनिर्धारित क्रेडिट अंक आपको दिए जाएँगे। संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा क्रेडिट के आधार पर पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

3. रचनात्मक क्रियास्थल

भारत मे परिवर्तन लाएं– यह जगह जनता को अपने रचनात्मक विचार प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से आप विभिन्न सरकारी विभागों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। समय–समय पर विभिन्न मंत्रालयों को अपनी पहलों के रचनात्मक संबंधी पहलुओं के लिए सुझाव चाहिए होते हैं। इस कार्य के अंतर्गत आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन से लेकर उसके मसौदा बैनर/प्रतीक चिन्ह और पहलों के प्रचार वाक्य से संबंधित सुझाव देने होंगे।

4. "मेरी सरकार" ब्लॉग

ब्लॉग पोर्टल के सभी समूह के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। जनता ब्लॉग के माध्यम से विभिन्न समूह की पहलों और सदस्यों द्वारा किये गए योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समूह के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा यह ब्लॉग आपको "मेरी सरकार" की प्रतियोगिताएं, अभियानों, विजेताओं इत्यादि सभी नवीनतम घटनाओं के बारे जानकारी प्रदान करता है।

5. आगे की योजना

यह पोर्टल सुशासन प्राप्त करने के लिए नागरिक सहभागिता जैसे बड़े लक्ष्य की ओर बढाया गया एक छोटा सा कदम है। समय के साथ समूह, कार्यों और चर्चाओं की संख्या बढ़ेगी। पोर्टल का प्रयोग एक व्यापक ज्ञान भंडार के रूप में किया जाएगा जहाँ भारत के प्रतिभाशाली लोग अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे।

शासन में नागरिक भागीदारी होने से विकास प्रतिमान में नागरिकों द्वारा होने वाला विकास शामिल है जो उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में देखता है द्य इसके अन्तगर्त विकास " ऊपर से नीचे की ओर" से नीचे से ऊपर की ओर" का बदलाव शामिल है, जिसमें केंद्रीय सरकार से दूर और आधारभूत स्तरों अर्थात सहायिकता के निकट, शक्ति का बढ़ता विकेंद्रीकरण सम्मिलित है। नागरिक भागीदारी नागरिक के जीवन, उनके व्यवसाय और उनके समुदायों को प्रभावित करेगी द्य इसके द्वारा नागरिक संसाधनों और निर्णय–निर्माण को प्रभावित कर उन पर नियंत्रण कर सकते है जो सीधे ही उनके जीवन को प्रभावित करते है। वैचारिक स्तर पर, शासन में नागरिक की सीधी सहभागिता एक स्वस्थ प्रजातंत्र का निर्माण करती है क्योकिं इसे प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र के पारम्परिक रूप को सुधाकर एक अधिक प्रतिक्रियाशील भागीदारीपूर्ण आधारभूत प्रजातन्त्र का निर्माण शामिल हैं।

अब यह व्यापक रूप से स्वीकारा जाता है कि सक्रिय नागरिक भागीदारी से सुशासन में निम्न प्रकार का योगदान सकता है –

1. यह नागरिक को जवाबदेही की मांग करने में समर्थ बनाती है और सरकार को अधिक प्रतिक्रियाशील कुशल व प्रभावी बनाती है।
2. यह सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को और अधिक प्रभावी व सतत बनाती है।
3. यह गरीबों लोगों को सरकारी नीति और सेवा सुपुर्दगी को उनका जीवन सुधारने के लिए प्रभावित करने में समर्थ बनाती है।
4. यह स्वस्थ, आधारस्तरीय प्रजातन्त्र को प्रोन्नत करती है।

निष्कर्ष

भारत में सुशासन के लिए नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित करने में कई प्रकार की समस्याएं है जो नागरिक सहभागिता में बांधा डालती है जैसे – अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, गरीबी, आधारभूत संरचना का अभाव आदि। उक्त समस्याओं पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए तथा लोगों में सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए द्य एक बेहतर लोकतांत्रिक देश का निर्माण उस देश के नागरिकों द्वारा ही किया जाता हैं। सुशासन के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के सन्दर्भ में द्वितीय प्रशासनिक आयोग के निम्न सुझाव दिए है –

1. प्रत्येक विभाग/सार्वजनिक एंजेंसी को सर्वप्रथम शासन में नागरिक भागीदारी के लिए विद्यमान पध्दतियों का आकलन किया जाना चाहिए।
2. जहां आवश्यक हो, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संशोधन करना चाहिए ताकि नागरिक भागीदारी के पर्याप्त " खिड़कियों" का विकास हो।
3. सरकार में नागरिक भागीदारी की संस्थागत बनाने का काम एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए।
4. वरिष्ठ अधिकारियों की निष्पादन प्रबंधन समीक्षाओं के अन्तगर्त शासन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका को शामिल किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सिफारिशों को सरकार ध्यान में रखकर इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योकिं बिना नागरिक सहभागिता के सुशासन के लक्ष्य को निःसंदेह नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. सिन्हा. एम (2010). " प्रशासन एवं लोकनीति". आसिफ अली रोड. नई दिल्ली. ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटिड.
2. शर्मा, एम.पी. सदाना, बी. एल एवं कौर हरप्रीत. (2013). " लोक प्रशासनः सिद्धान्त एवं व्यवहार". हरि सदन, दरियागंज, नई दिल्ली, किताब महल.
3. राव, एन. भास्कर. (2017). "सुशासन". मोहन कॉपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया. मथुरा रोड, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन.
4. अवस्थी एवं माहेश्वरी. (2012). "लोक प्रशासन". अनुपम प्लाजा, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
5. फड़िया, बी. एल. (2014). " लोक प्रशासन". आगरा, साहित्य भवन.
6. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम रिपोर्ट – "सूचना का अधिकार रू सुशासन के लिए मास्टर कुंजी", Retrieved from- https://darpg.gov.in/arc-reports
7. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बारहवाँ रिपोर्ट– "नागरिक – केंद्रित प्रशासन" Retrieved from- https://darpg.gov.in/arc-reports
8. मेरी सरकार पोर्टल, Retrieved from - https://www.mygov.in/hi/simple-page
9. न्यू इंडिया समाचार. "सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण (1 जून 2022)". वर्ष –2, अंक– 23.
10. "सुशासन के 20 साल" Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://transformingindia.mygov.in/wp-content/uploads/2021/10/Social-Empowerment-including-Divyang-hindi-compressed.pdf&ved=2ahUKEwjahcXG25n6AhXRgeYKHQDyCJE4FBAWegQIBRAB&usg=AOvVaw1jxEIsCggrrlglHEhk4B7j